



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 श्रावण 1938 (श10)

(सं0 पटना 657) पटना, बृहस्पतिवार, 11 अगस्त 2016

सं० 2/नि0कां0- 301/2007-सा0प्र0-10532

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 अगस्त 2016

श्री आनन्द स्वरूप (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 491/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, आदापुर, पूर्वी चम्पारण को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 10.02.2007 को परिवादी श्री गोपीचन्द्र राम से 5000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर निगरानी थाना कांड संख्या 017/2007 दिनांक 11.02.2007 दर्ज किया गया।

2. आरक्षी उप-महानिरीक्षक, अन्वेषण ब्यूरो, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 166 दिनांक 14.02.2007 द्वारा प्रतिवेदित उपर्युक्त सूचना के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3271 दिनांक 26.03.2007 द्वारा दिनांक 11.02.2007 के प्रभाव से श्री स्वरूप को निलंबित किया गया।

3. श्री स्वरूप को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर श्री स्वरूप के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5554 दिनांक 11.06.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

5. विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक 347 दिनांक 16.07.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या-2 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

6. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के संगत प्रावधान के तहत प्रमाणित आरोप के लिए श्री स्वरूप से अभ्यावेदन की मांग किये जाने पर उनके द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 07.09.2015 समर्पित किया गया।

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री स्वरूप के स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया तथा इसे अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 के संगत प्रावधान के तहत सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड अधिरोपित किये जाने का विनिश्चय किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित दंड पर सहमति व्यक्त की गयी। मंत्रिपरिषद् के निर्णयोपरांत श्री स्वरूप को संकल्प ज्ञापांक 4295 दिनांक 18.03.2016 द्वारा **सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड** संसूचित किया गया।

8. श्री स्वरूप द्वारा उक्त दंडादेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 29.04.2016 समर्पित किया गया। श्री स्वरूप का कहना है कि शिकायत पत्र प्राप्त होने से लेकर ट्रेप की कार्यवाही निष्पादित होने तक कभी यह जानने का प्रयास निगरानी ब्यूरो द्वारा नहीं किया गया कि शिकायत पत्र में जिन लोगों पर जो आरोप लगाये गये हैं, वे उनसे संबंधित है या क्षेत्राधिकार में है या नहीं। विभागीय पत्रांक 945 दिनांक 24.06.2005, जो सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त

बेनामी एवं छद्मनामी परिवार पत्रों पर कार्रवाई से संबंधित है, को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पूरी तरह नजर अंदाज किया गया है। सुदामा राम एवं गोपीचन्द्र राम के पंचायत शिक्षक नियोजन के मामले में सभी कार्रवाईयाँ पंचायत स्तर से हुई। सत्यापनकर्ता विनोद कुमार प्रसाद, स0अ0नि0 दिनांक 09.02.2007 (कथित सत्यापन की तिथि) को निगरानी मुख्यालय, पटना में ही थे। दिनांक 09.02.2007 को प्रखंड विकास पदाधिकारी का कोई सत्यापन नहीं किया गया, बल्कि झूठा एवं बनावटी सत्यापन प्रतिवेदन तैयार कर समर्पित किया गया। इसी झूठे प्रतिवेदन को आधार बनाकर ट्रैप की कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। निगरानी विभाग द्वारा अगर घटनास्थल पर सही रूप से स्वतंत्र गवाहों को चुना जाता तो उनके कुकृत्य एवं गलत ढंग से की जा रही कार्रवाईयों का भंडाफोड़ हो जाता इसलिए वाद में निश्चित एवं निर्धारित गवाह रखा गया था। विभागीय कार्यवाही एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है, अतः तथाकथित स्वतंत्र गवाहों का भी बयान लिया जाना एवं इनका प्रतिपरीक्षण किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। पंचायत सचिव के पत्र का उत्तर ज्ञापांक-6/आ0 दिनांक 03.02.2007 द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त करा दिया गया, फिर भी गोपीचन्द्र राम के नियोजन को लटकाये रखने का आरोप लगाया गया, जो पूर्णतः निराधार एवं बेबुनियाद है। संचालन पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा वांछित पत्र को न प्रस्तुत किया गया, न इसके संबंध में किसी प्रकार की सूचना दी गयी। विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा उनके द्वारा प्रतिवादी का किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवारी द्वारा दिये गये उत्तरों को कोई संज्ञान नहीं लिया गया, बल्कि उसे पूर्णतः ignore किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं की गयी। उनके मामले में बहुत सारे ऐसे तथ्य थे, जिसके आधार पर आयोग द्वारा उनके पक्ष में परामर्श दिया जा सकता था, जो नहीं दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में प्रपत्र 'क' के दोनों आरोपों की जाँच की गयी है, पर अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोप संख्या-2 को प्रमाणित बताया गया एवं आरोप संख्या-1 के संबंध में स्वतंत्र जाँच कराने की अनुशंसा की गयी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उनके मामले में बिहार लोक सेवा आयोग से लिए गये परामर्श पर उनका कोई मतव्य नहीं लिया गया, जो नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है और संविधान के **Mandatory** अनुच्छेद 320(3)(c) के साथ नियमावली, 2005 के नियम 21 का उल्लंघन है। वर्णित तथ्यों के आधार पर उनके विरुद्ध पारित बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

9. प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री स्वरूप की पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा की गयी। संचालन पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा के उपरान्त प्रतिवेदित किया गया कि श्री स्वरूप द्वारा अनावश्यक और नियमविरुद्ध तरीके से परिवारी के मामले को लंबित रखा गया। इस आधार पर परिवारी के परिवार को सत्य पाया गया। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर कार्यरत आरोपित पदाधिकारी के समक्ष उनके प्रखंड के ही एक अन्य उनसे कनीय पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी लगातार रिश्त की मांग करते रहे थे इसलिए आरोपित का यह प्रशासनिक ही नहीं बल्कि वैधिक दायित्व भी था कि ऐसे रिश्त मांगने वाले पदाधिकारी, कर्मचारी पर अविलम्ब क्रिमिनल कार्रवाई करने तथा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए वे बिना चूक के उचित कदम उठाते। ऐसा कुछ भी नहीं कर के वे मूकदर्शक बने रहे, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ होता है कि वे इस रिश्त मांगने की कार्रवाई में सहभागी थे।

संचालन पदाधिकारी के द्वारा सभी तथ्यों की गहन जाँच एवं समीक्षा के उपरान्त श्री स्वरूप के विरुद्ध रिश्त लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने संबंधी आरोप को पूर्णतः प्रमाणित पाया गया है।

10. वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री स्वरूप के पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 29.04.2016 को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4295 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा निर्गत दंड "सेवा से बर्खास्तगी एवं निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने" को पूर्ववत् बरकरार रखने का विनिश्चय किया गया।

11. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आनन्द स्वरूप सम्प्रति सेवा से बर्खास्त के पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक 29.04.2016 को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4295 दिनांक 18.03.2016 के द्वारा निर्गत दंड "सेवा से बर्खास्तगी एवं निलम्बन अवधि के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने" को पूर्ववत् बरकरार रखा एवं संसूचित किया जाता है।

12. अनुशासनिक प्राधिकार के उपर्युक्त विनिश्चय पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री आनन्द स्वरूप (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त), द्वारा-बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल, मुहल्ला-बलुआ टाल (कुशवाहा छात्रावास के नजदीक), पो0-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण-845401 एवं सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 657-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>